आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 45 (प्रति रविवार) इंदौर, 28 जुलाई से 03 अगस्त 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

मनु भाकर ने जीता ओलंपिक मेडल, देश में खुशी का माहौल, पीएम मोदी बोले- यह एक ऐतिहासिक पल

नई दिल्ली। *पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटर बन गई हैं। उनकी सफलता पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है।*

मनु भाकर की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी है।

भारत के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वह शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी उपलब्धि कई खिलाड़ियों, विशेषकर

महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करता हूं कि वह भविष्य में और अधिक उपलब्धियां हासिल करें।

पीएम मोदी ने कहा- शाबाश मनु भाकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि एक ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने के लिए शाबाश मनु भाकर। आपको कांस्य पदक के लिए बधाई। यह सफलता और भी खास है, क्योंकि वह भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक अविश्वसनीय उपलब्धि।

अमित शाह ने दी मनु भाकर को बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर पहला पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई। आपने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। देश को आप पर गर्व है।

चाचा बलजीत सिंह ने शुरू की स्वागत की तैयारी

निशानेबाज मनु भाकर के चाचा बलजीत सिंह ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। हम स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। पूरा गांव उनका स्वागत करेगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बहुत मेहनत की है।

एक अगस्त से बदलेंगी रोजमर्रा की व्यवस्थाएं, गैस सिलेंडर, बिजली और पानी का बिल भरना हो सकता है महंगा

नई दिल्ली। *पहली अगस्त से इस बार कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर लोगों की जेब के अलावा आदतों पर भी पड़ेगा। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव के साथ बैंकिंग कामकाज भी है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे और बिजली, पानी और गैस का बड़ी राशि का बिल भरना भी महंगा हो जाएगा।*

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। 1 अगस्त को भी कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय होंगी। पिछले महीने सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की थी। इस बार भी उम्मीद है कि सरकार गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव कर सकती है। यह बदलाव घर के बजट को प्रभावित कर सकता है।

एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे-बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। किराए का भुगतान करने के लिए सीआरईडी, चेक, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज जैसी सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को ट्रांजेक्शन राशि पर 1 प्रतिशत चार्ज देना होगा। यह चार्ज प्रति लेनदेन 3000 रुपये तक सीमित रहेगा। पेट्रोल-डीजल की खरीद पर भी नए नियम लागू होंगे। 15 हजार रुपए से कम के लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन, इससे ज्यादा के लेनदेन पर पूरी राशि पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जो अधिकतम 3 हजार रुपए होगा।

यूटिलिटी बिलों का भुगतान महंगा-बिजली, पानी, गैस आदि के बिलों के भुगतान पर भी नए नियम लागू होंगे। 50 हजार रुपए से कम के लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे अधिक के लेनदेन पर पूरी राशि पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जो प्रति लेनदेन 3 हजार रुपए तक सीमित रहेगा।

गूगल मैप में बड़ा बदलाव-गूगल मैप ने भारत में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कंपनी ने अपनी सेवाओं के शुल्क को 70 प्रतिशत तक कम कर दिया है। साथ ही, अब गूगल मैप अपनी सेवाओं के लिए डॉलर की जगह भारतीय रुपये में भुगतान लेगा। हालांकि, यह बदलाव आम उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

भुगतान में देरी और ईएमआई पर शुल्क-एचडीएफसी बैंक ने देर से भुगतान के शुल्क को भी संशोधित किया है। अब यह शुल्क 100 रुपये से 1,300 रुपये तक हो सकता है, जो बकाया राशि पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर ईजी-ईएमआई का विकल्प चुनने पर 299 रुपये तक का ईएमआई प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा।

टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड में बदलाव-बैंक अपने टाटा न्यू इंफिनिटी और प्लस क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव करेगा। 1 अगस्त से, टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं को टाटा न्यू यूपीआई आईडी का उपयोग करके किए गए योग्य यूपीआई लेनदेन पर 1.5 प्रतिशत न्यूकॉइन्स मिलेंगे।

राहुल को हुआ मोची की तकलीफ का एहसास, भिजवा दी सिलाई मशीन

सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब राजनीति में परिवक्व हो गए हैं। वे गरीब तबके से मिलते हैं,बात करते हैं और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। सुल्तानपुर से पेशी के लौटते वक्त राहुल गांधी ने मोची की दुकान के सामने गाड़ी रुकवाई, वहां गए और जूते चप्पल ठीक कर रहे रामचेत से बात की। इस दौरान रामचेत की आंख से खुशी के आंसू छलक पड़े। इसके बाद राहुल ने रामचेत को जूते-चप्पल सिलने की मशीन भिजवाई है। इस मशीन से वह अपने काम को आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से लौटते वक्त राहुल गांधी ने मोची रामचेत की दुकान पर रुके थे और उनसे बातचीत की थी।

राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि के मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से पहले अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर कूरेभार थानाक्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास अचानक से उनका काफिला रुका और वे गाड़ी से उतरकर रामचेत नाम के एक मोची की दुकान की ओर चल पड़े थे। इस दौरान वह दुकान पर रामचेत के बगल बैठे और हालचाल लिया। साथ ही उन्होंने रोजगार और रामचेत के घर का भी हाल जाना। करीब 40 सालों से जूते बनाने की दुकान चला रहे रामचेत से राहुल की मुलाकात कुछ देर तक चली। रामचेत राहुल गांधी को देखकर फूट-फूटकर रोने लगे थे। सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी ने मोची रामचेत के अलावा लोको पायलट्स से भी मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना था।

संपादकीय

538 लोकसभा सीटों पर पड़े वोट और गिने गए वोटों पर अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने सोमवार को एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है। 362 लोकसभा की सीटों पर मतदाताओं द्वारा डाले गए और गिने गए वोटो में 5,54,598 वोटो का अंतर है। मतगणना कम वोटों की की गई है। जबकि जीतने वाले प्रत्याशी और दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। इससे जीत-हार प्रभावित हुई है। लोकसभा की 176 लोकसभा सीटों पर वोट कम पड़े और 35093 वोट ज्यादा गिने गए हैं। 538 सीटों पर कुल वोटों का अंतर 5,89,691 पाया गया है। इस संस्था के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा है, कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदान का डाटा जारी करने में भी पारिदर्शिता नहीं बरती गई है। चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के आंकड़े काफी विलंब से जारी किए गए। प्रारंभिक मतदान और अंतिम मतदान के परिणामों में 5 करोड़ से अधिक वोटों का अंतर पाया गया है। अभी भी चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना के आंकड़े मतदान केंद्र के हिसाब से जारी नहीं किए गए हैं। इस कारण लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना को लेकर संदेह बना हुआ है। जबकि यह जानकारी पूर्व में चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही थी। एडीआर ने 79 लोकसभा सीटों का एक अलग विश्लेषण जारी किया है। जिसमें मतदान कम होने की जानकारी दी गई थी। जब मतगणना हुई, उसमें करोडों वोट ज्यादा गिने गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के बीच में आदर्श आचार संहिता की जो शिकायतें की गई थीं, उन पर भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा शिकायतों का भेदभाव पूर्ण ढंग से निपटारा करने का आरोप लगा है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार पक्षपात और संदेह व्यक्त किया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायाधीश, वकील और पत्रकार भी शामिल हैं। यह संस्था पिछले कई वर्षों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का डाटा इकट्ठा करती आ रही है। उसका विश्लेषण करती है, और समय-समय पर वह डाटा सार्वजनिक पोर्टल पर जारी करती है। इस संस्था की बड़ी विश्वसनीयता मतदाताओं, मीडिया और संस्थाओं के बीच में बनी हुई है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध डाटा के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए गड़बड़ियों को उजागर करती है। समय-समय पर इस संस्था द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सकें, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करती है। 5 वर्ष पहले भी इस संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के कारण डिटेल में जाकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में ईवीएम मशीन, बीवीपेट मशीन, बीवीपेट से निकली हुई मतदान पर्चियों की गिनती, माइक्रोकंट्रोल यूनिट इत्यादि के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किए थे, उसका पालन भी चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत नहीं किया गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था। उसको बदलते हुए सरकार ने एक नया कानून बनाया। जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, और नेता प्रतिपक्ष के तीन सदस्यों की कमेटी ने चुनाव के ठीक पहले तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। यह नियुक्ति भी विवादों में है। नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों ने शपथ भी ले ली है। सरकार का गठन भी हो गया है। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है। संगठन ने चुनाव आयोग से भी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जानकारी देने के स्थान पर छुपाया जा रहा है। इससे भी संदेह बढ़ रहा है।

मौत बांटते असुरक्षित कोचिंग सैंटर, पीजी और हॉस्टल

ललित गर्ग

दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत-हादसे ने समूचे राष्ट्र को दुःखी एवं आहत किया है, यह हादसा नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, लापरवाही एवं लोभ की पराकाष्ठा है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर दोषग्रस्त कोचिंग प्रणाली और व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। इस दुःखद एवं पीड़ादायक घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। जिसकी कीमत निर्दोषों को अपनी जान गंवा का चुकानी पड़ रही है। निश्चित ही देशभर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए कोचिंग सैंटर डैथ सैंटर बन चुके हैं। कोचिंग सैंटरों का कारोबार शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। छात्रों को सुनहरी भविष्य का सपना दिखा कर मौत बांटी जा रही है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। प्रश्न है कि सैंटर के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन ऐसी घटनाओं के दोषी अधिकारी क्यों नहीं गिरफ्तार होते?

शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के कोचिंग सैंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डोल्विन, तान्या सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खड़ा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आईएएस की तैयारी कर रहा था और वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव ने अभी एक महीना पहले ही इस कोचिंग सैंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जहां 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। हादसे के वक्त 35 छात्र मौजूद थे। चंद मिनटों में ही बेसमेंट में पानी भर गया। सिर्फ इसी सैंटर में नहीं, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। जिसके गेट बायोमेट्रिक आईडी से खुलते हैं, जैसे ही बारिश होती है, बिजली चली जाती है, उसके बाद बेसमेंट से निकलना बिना बायोमैट्रिक आईडेंटिफिकेशन के मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हादसे और मौत की संभावना बढ़ जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर के न सिर्फ कोचिंग सैंटर बल्कि पीजी और हॉस्टल की असुरक्षित हालत भी मौत लिये किसी भी क्षण बड़े हादसे की संभावना के साथ खड़ी है। जहां इस कदर अवैध निर्माण है कि कभी भी दूसरा या दोबारा हादसा हो सकता है। इसलिये ऐसे हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला।

विडम्बनापूर्ण है ऐसे जलभराव एवं आगजनी के हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है। राजधानी में रह-रह कर एक के बाद एक हो रहे हादसों के बावजूद दिल्ली-सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक एम्यूजमेंट पार्क के अंदर गेमिंग जोन में लगी आग की लपटें हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बच्चों के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगना और अब कोचिंग सैंटर में तीन होनहार एवं देश के भविष्य बच्चों का दर्दनाक तरीके से डूबकर मर जाना-निश्चित रूप से ये हादसे प्रशासनिक लापरवाही की उपज हैं, यही कारण है कि सिस्टम में खामियों और ऐसी आपदाओं को रोकने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की निंदा भी व्यापक स्तर की जा रही है। यह याद रखने योग्य है कि नियमित अंतराल पर मानवीय जिम्मेदारी वाले पहलू की अनदेखी से ऐसी गंभीर घटनाएं होने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही कम होती नहीं दिख रही है। इन त्रासद हादसों ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए।

परिवार वालों ने और छात्रों ने स्वर्णिम भविष्य के सपने संजो कर और लाखों की फीस देकर कोचिंग शुरू की होगी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। छात्रों की मौत को महज हादसा नहीं माना जा सकता, यह एक तरह से निर्मम हत्या है और हत्यारा है हमारा सिस्टम। हादसे से आक्रोशित छात्रों का कहना है कि वे 10-12 दिन से दिल्ली नगर निगम से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई कारवाई जाए लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हादसे तभी होते हैं जब नियमों और कानूनों को ताक पर रखा जाता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलते ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। जलभराव क्यों और कैसे हुआ, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन इन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को उसके मालिकों ने मौत का कुआं बना रखा था। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है। हर दुर्घटना में गलती भ्रष्ट आदमी यानी अधिकारी एवं व्यवसायी की ही होती है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद ही उन पर कार्रवाई क्यों होती है? सरकार पहले क्यों नहीं जागती?

वैसे तो बेसमेंट में कोचिंग सैन्टर या लाइब्रेरी चलाना गैर-कानूनी है, इस घटना के सन्दर्भ जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। जलभराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 30-35 छात्र थे। यह तो गनीमत रही कि तीन अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे-तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जलभराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एमसीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ-साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है।

बात हम नया भारत एवं विकसित भारत की करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं बनी है और हम अनियंत्रित एवं असुरक्षित विकास करते जा रहे हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, चैन्नई या बेंगलुरु या ऐसे ही अन्य बड़े शहर -हर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। दिल्ली के इनकम टैक्स भवन में आग से एक अधिकारी की जान हाल में गयी। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक हैं या निर्दोषों को परेशानी करने के लिये है। औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े-बड़े दावे करने और उन्हें संवारने की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त एवं असुरक्षित हैं। हर हादसे पर सियासत होती है लेकिन कोचिंग सैंटर माफिया इतना ताकवर है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता।

शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय पर्यटन प्रतियोगिता में 320 से अधिक विद्यालयों ने की सहभागिता

इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के अध्यक्ष आशीष सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में इस वर्ष मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद इंदौर एवं स्कूल शिक्षा विभाग इंदौर के द्वारा शनिवार 27 जुलाई को जिला स्तरीय पर्यटन क्विज का सफल आयोजन किया गया।

मेडिकैप्स विश्वविद्यालय राऊ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 320 से अधिक विद्यालयों के 3 प्रतिभागियों की टीमें सम्मिलित हुई। यह एकमात्र आयोजन है, जिसमें जिले के सर्वाधिक विद्यालय सहभागिता करते हैं। इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक सम्मिलित संख्या इंदौर जिले से थी।

प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हल करने की प्रतियोगिता हुई। दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य मूल्यांकन कार्य एवं सम्मिलित प्रतिभागियों हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एवं भोजन प्रदाय किया गया।

प्रथम 6 दल का मेरिट आधार पर चयन कर द्वितीय चरण की मल्टी मीडिया क्विज, क्विज मास्टर आरके चेलानी द्वारा आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता शिशु कुंज इंटरनेशनल स्कूल इंदौर, द्वितीय उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर इंदौर तथा तृतीय सीएम राइज अहिल्याश्रम क्रमांक 1 इंदौर रही। उपविजेता टीमों में प्रथम शा. अत्री देवी उमावि सुदामा नगर, इंदौर, द्वितीय एडवांस अकादमी तथा तृतीय न्यू पिंक फ्लावर उमावि, नेहरू नगर, इंदौर रही। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा वैश्य एवं डाइट प्राचार्य मंगलेश व्यास द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया। सभी विजेता दलों को कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के अध्यक्ष आशीष सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के सचिव सिद्धार्थ जैन, संचालक पर्यटन विभाग अजय श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक भदौरिया एवं मेडिकैप यूनिवर्सिटी के डॉ. दिलीप पटनायक द्वारा विजेताओं को बधाई दी गई। प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में मैडल प्रदाय किया गया। साथ ही विजेता टीमों को मध्यप्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल का पर्यटन कराया जायेगा। जिसमें विभाग के होटल में प्रथम 3 टीमों को 3 दिन, 2 रात ठहराया जायेगा। इसी तरह द्वितीय 3 टीमों को 2 दिन और 1 रात ठहराया जाएगा। गाइड सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रथम स्थान प्राप्त दल शिशु कुंज इंटरनेशनल के प्रतिभागी अर्गया शर्मा, शौर्य परमार, अर्यमा मिश्रा राज्य स्तर पर इंदौर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन में मेडिकैप्स विश्वविद्यालय ने सहयोग प्रदान किया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित, कहा

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी समूहों सहित अन्य सभी का ध्यान रखने वाला बजट

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

इन्दौर। जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज जब भारत आगामी वर्ष 2047 में आजादी की 100 वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आगे बढ़ रहा है ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उच्च आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

यह हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और उनके नेतृत्व में भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2024-2025 उसी लक्ष्य को परिलक्षित करता है। यह बजट मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गये विश्वास को दर्शाता है। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आगे कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी समूहों सहित अन्य सभी का ध्यान रखा गया है।

इस बजट में विकास के 9 सूत्रीय विषय को शामिल किया गया है जो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन से लेकर अगली पीढ़ी के सुधारों तक सर्वांगीण और समग्र कल्याण तथा विकास को समाहित करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पाँच वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए पाँच योजनाओं और पहलों का एक पैकेज घोषित किया गया है जिसका केन्द्रीय आबंटन 2 लाख करोड़ रुपए है ।

ईपीएफ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रतिपूर्ति समर्थन दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है जिससे 50 लाख से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचेगा । इस बजट में कौशल विकास हेतु जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसके तहत पाँच वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए देश के 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और इससे संबंधित पाठ्यक्रम की सामग्री को आधुनिक समय की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को ई-वॉउचर प्रदान किए जाएंगे जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान होगा। इसके अलावा सरकार ने युवाओं को 500 कंपनियों में उद्योग का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू करने का प्रावधान किया है जिसमें आगामी पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा। पहली बार नौकरी में आए कर्मियों को 15000 रुपए तक का एक महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिससे 2.01 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। देश के बेहतर कल के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। साथ ही डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत बढ़ाने के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। माध्यम वर्ग के लिए असमानताओं को कम करने के लिए बजट में सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए गए हैं जिसमें एनपीएस की कटौती की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है और एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत की गई है। बजट में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदान किया गया है । सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत का अमृत काल उसका कर्तव्यकाल भी है इसके दौरान समाज के सभी वर्गों जिसमे गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति है इन सभी को राष्ट्र की सफलता की कहानी में आपना योगदान देना है। इसके साथ ही देश के आदिवासी समुदायों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए देश के 63,000 गावों को कवर किया गया है जिसका देश के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा ।

संविधान हत्या दिवस से हत्या शब्द हटाने के लिए बनाई मानव श्रृंखला

इंदौर। देश में लगे आपातकाल अवधि से प्रभावित लोगो श्रद्धांजलि देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है । डॉ. अम्बेडकर युग सेवा समिति सहित अन्य डॉ. अम्बेडकर अनुयायी व संविधान में आस्था रखने वाले लोगो को संविधान हत्या दिवस में हत्या शब्द पर आपत्ति है। संविधान हत्या दिवस से हत्या शब्द हटाने की मांग को लेकर रविवार को इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित डॉ. अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर भारी बारिश में डॉ. अम्बेडकर युग सेवा समिति के नेतृत्व में मानव श्रंखला बनाई गई। उनका कहना है की भारत का संविधान जीवित है और देश में सबके बीच मौजूद है । इसलिए तर्क व तकनिकी तौर पर संविधान हत्या दिवस में हत्या शब्द सही नहीं है । उक्त मांग को लेकर पूर्व में समिति द्वारा सांसद शंकर लालवानी को प्रधानमंत्री के नाम व इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जा चूका है । मानव श्रंखला में सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर राहुल मेटांगे, भीमराव सरदार, रघुवीर मरमट, भारत निम्बाड़कर, लक्की पिसे, लोकेश इन्द्रे, विनोद ठाकरे, राज सावनेर, मार्शल योगेश भवते, मार्शल तिथि रामटेके, दीक्षा भवते, कैलाश मोटघरे, उमेश लोदवाल, रविंद्र गुरुचल, गौतम खण्डेराव, कुणाल वाकोड़े, प्रकाश निकड़े, मुकुल वाघ, सुधाकर वाघ, आनंद वाघ, रणजीत गोहर, लीलाधर वर्मा, राकेश बंदावड़े, कृष्ण कुमार जाटवा, जितेंद्र ठाकरे, राहुल जाधव, अनिल इंगले, विकास भीमके, राजेश भालेकर, हेमंत वासनिक, संतोष गवांदे, सुरेश वानखेड़े, डॉ. नयन इंगले, डॉ. जयभान सिंह पवय्या, डॉ. समरथ मचार, रणजीत डागर, निर्मल रोकड़े, शुभम बिल्लोरे, अमित मेश्राम, प्रभाकर बोरकर, दिलीप वासनिक, देवांशु नागदीवे, धरम जी, प्रभाकर मोहद सहित अन्य अम्बेडकर अनुयायी मौजूद थे।

भाजपा के निष्ठावान वरिष्ठों को मिलेगी निगम-मंडलों की कुर्सी

पार्टी हाईकमान ने दी हरी झंडी, नेताओं की भाग दौड़ शुरू

भोपाल।*प्रदेश में करीब छह माह से निगम-मंडल-प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की राह देख रहे नेताओं की जल्द ही लॉटरी लगने वाली है। भाजपा हाईकमान ने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही कहा गया है कि निष्ठावान वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडल और प्राधिकरणों में पदस्थ किया जाए।*

इन दिनों प्रदेशभर के भाजपा नेताओं के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के फेरे बढ़ गए हैं। यह नेता अपने साथ अपनी उपलब्धियों के ब्यौरे के साथ ही पूर्व में मिले आश्वासनों का पुलिंदा लेकर भी चल रहे हैं। उन्हें सत्ता में भागीदारी के लिए जो नेता मददगार साबित होने वाला लगता है, उसे अपनी बायोडाटा वाली फाइल थमा दी जाती है। यह वे नेता हैं, जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दावेदारी के बाद भी टिकट नहीं दिया गया था। यही वजह है कि अब यह नेता चाहते हैं कि उन्हें निगम मंडल में भागीदारी मिल जाए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से निगम मंडलों में अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। पार्टी हाईकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है।

निगम-मंडलों में उन सीनियर नेताओं की नियुक्ति की जाएगी जो पार्टी में लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और उन्हें अब तक कोई बड़ा पद नहीं मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े नेताओं को भी तरजीह दी जाएगी। भाजपा ने इसके लिए संघ से भी दस नाम मांगे हैं। वहीं प्रदेश संगठन भी अपनी सूची तैयार कर रहा है। जिस पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट के गठन के बाद सभी निगम मंडलों को भंग कर दिया गया था।

दावेदारों की बढ़ रही बेचैनी

गौरतलब है कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे कि जिन नेताओं ने चुनाव में अच्छा काम किया है और पार्टी के हर फैसले के साथ रहे हैं। पार्टी उनका पूरा ख्याल रखेगी। इसके बाद से ही निगम मंडलों में पदों पर नियुक्ति को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। इनमें अधिकांश वे नेता शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव के समय किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित कर दिए गए थे पर उन्होंने बगावती तेवर न अपनाते हुए पार्टी द्वारा तय प्रत्याशी के पक्ष में पूरे मन से काम किया। ऐसे वरिष्ठ नेता अब निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में अपनी तैनाती चाहते हैं। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर दावेदारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। टिकट पाने से वंचित रह गए जिन नेताओं के नसीब में आश्वासन आए थे वे इन नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन और चुनाव के कामों में सालों से लगे नेताओं को भी अपने काम के इनाम का इंतजार है। इसके अलावा कांग्रेस से चार साल पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान अपने समर्थकों के साथ आए नेताओं को भी अपने राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार है।

नियुक्ति का खाका तैयार

सूत्रों की मानें तो दिल्ली में इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा कर चुके हैं। निगम, प्राधिकरण, आयोग समेत चार दर्जन सार्वजनिक उपक्रमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सदस्य अथवा संचालक मंडल में नियुक्तियां होनी हैं। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि इनके दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है और पार्टी को नाम तय करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं संघ भी अपने कोटे के दस नामों पर विचार कर रहा है। इसमें अधिकांश वे नेता शामिल हैं जो संघ से भाजपा में गए हैं।

शिवराज सरकार में संभागीय संगठन मंत्री के दायित्व से मुक्त किए गए आधा दर्जन से अधिक नेताओं को निगम मंडल में पदों से नवाजा गया था। इनमें आशुतोष तिवारी, शैलेन्द्र बरूआ, जितेन्द्र लिटौरिया जैसे नेता शामिल थे। तब इन्हें आरएसएस के कोटे से ही माना गया था। इस बार इनकी जगह नए नामों पर संघ विचार कर रहा है। निगम मंडलों में दो बार रह चुके नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नए चेहरों को मौका देने के लिए किया जा रहा है। संगठन से जुड़े एक बड़े नेता की मानें तो इस बार ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को निगम मंडल और प्राधिकरणों में जगह दी जाएगी। दरअसल पार्टी हाईकमान को कई नेताओं ने लिखित में भेजा है कि कुछ चेहरों को हर बार निगम मंडल में कोई न कोई पद दिया जाता है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो नेता दो बार निगम मंडल या प्राधिकरणों में ताजपोशी पा चुके हैं, उन्हें अब और मौका नहीं दिया जाएगा। संगठन के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर काम किया है, उन्हें इस बार प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसमें प्रदेश से लेकर जिलों तक के नेता शामिल है।

10 लाख की रिश्वत लेते घर में रंगे-हाथों पकड़ाया लोनिवि का अधीक्षण यंत्री

नर्मदापुरम। संभाग मुख्यालय नर्मदापुरम में करीब डेढ़ वर्षों से पदस्थ लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री आरसी तिरोले को उनके सरकारी आवास से रविवार शाम को लोकायुक्त टीम भोपाल द्वारा ठेकेदार की शिकायत पर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही के बाद पीडब्लूडी विभाग में पर हड़कंप मच गया है। लोक निर्माण विभाग का संभाग अधिकारी अपने ही घर पर रिश्वत का खुला खेल खेलता रहा और ठेकेदार परेशान और प्रताड़ित होकर अधिकारी की मनमानी के आगे झुके रहे। इसके बावजूद अत्यधिक परेशान और मजबूर होकर बैतूल के एक ठेकेदार ने अंततः लोकायुक्त की शरण लेकर पूरे रिश्वत के खेल का खुलासा करते हुए अधिकारी का चेहरा बेनकाब कर दिया। सूत्रों ने बताया कि अधीक्षण यंत्री अपनी एक टीम बनाकर कैसे ठेकेदार को प्रताड़ित करता था?और उनसे कैसे वसूली का खुला खेल खेलता था? सूत्र बताते हैं कि इस पूरे खेल में एक सेवानिवृत बाबू सहित कुछ अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में लोकायुक्त एसपी मनु व्यास के अनुसार- डीएसपी अनिल बाजपेई के नेतृत्व में टीम कार्रवाई कर रही है और वर्तमान में जांच जारी है। डीएसपी श्री वाजपेई के अनुसार- शनिवार 27 जुलाई को आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत किया कि उनके फर्म द्वारा मुलताई एवं भैंसदेही में आठ सड़कों का निर्माण कराया था। जिसमें शेष कार्य के एक्सटेंशन के लिए प्रकरण एसई नर्मदापुरम डिविजन पीडब्ल्यूडी आरसी तिरोले के पास लंबित है। जिसके निराकरण के लिए श्री तिरोले द्वारा 20 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। रविवार 28 जुलाई को श्री तिरोले अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम डिविजन को आवेदक से 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए उनके सरकारी आवास पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी जांच और कार्रवाई जारी है। टीम का नेतृत्व डीएसपी अनिल बाजपेई द्वारा किया जा रहा है।

टीम में डीएसपी संजय शुक्ला, निरीक्षक नीलम पटवा, निरीक्षक उमा कुशवाहा, प्रधान आरक्षक बृज बिहारी, पांडे आरक्षक राजेंद्र, पवन, आरक्षक मनमोहन साहू शामिल है। ट्रैप कार्यवाही समाचार लिखे जाने तक जारी रही। दूसरी तरफ कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त पुलिस टीम को सिटी पुलिस द्वारा नोट गिरने की मशीन भी उपलब्ध कराई गई। सूत्र बताते हैं कि ठेकेदारों से वसूली फर्जी एक्सटेंशन बनाकर की जा रही थी। लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही के बाद अब यह बात भी सामने आ रही है कि विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था? जिसकी परत दर परत अब जल्द सामने आएंगी।

कैरियर विकल्पों का चयन करने के लिये कैरियर पोर्टल बनाया

स्कूल शिक्षा विभाग के कैरियर पोर्टल पर महत्वपूर्ण जानकारियां

भोपाल।स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल जाने वाले विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार करियर विकल्पों का चयन करने के लिये करियर पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल पर 500 से अधिक करियर संबंधी, 7 हजार 500 से अधिक कॉलेज, 1000 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं और 750 से अधिक छात्रवृत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इससे विद्यार्थी अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक एवं करियर के विकल्पों के चयन के लिए करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था आईसीएस लखनऊ के साथ अनुबंध किया है। इस अनुबंध के आधार पर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। काउंसलिंग एवं गाइडेंस से संबंधित कौशल विकास के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित भी किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के लिये प्रत्येक जिले से 2-2 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना गया है और उन्हें आईसीएस पोर्टल और एप के उपयोग संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल ट्रेनर को प्रशिक्षण दिलाया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत एम्प्लॉयबिलिटी के लिये आवश्यक हार्ड- सॉफ्ट स्किल के विकास की जानकारी, आईसीएस करियर जीपीएस मोबाइल एप पर पंजीयन के बाद विद्यार्थियों को उनकी रूचि और एप्टीट्यूड के अनुसार करियर से संबंधित विकल्पों की जानकारी दी गई।

इस बार सरकारी विभागों को किस्तों में दिया जाएगा बजट

खर्च पर सरकारी पहरा लगाया जाएगा

भोपाल। *मप्र में सरकार इस बार बजट का उपयोग फूंक-फूंक कर करेगी। विभागों को किस्तों में बजट दिया जाएगा और उनके खर्च की मॉनिटरिंग की जाएगी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विभागों को बजट की राशि आवंटित की जाएगी। विभाग इस राशि का उपयोग अगस्त से मार्च 2025 तक खर्च कर सकेंगे।*

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को विधानसभा में मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट की राशि पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का पिछला बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का था। बजट भले ही 3.65 लाख करोड़ का है, लेकिन विभागों को 2.20 लाख करोड़ में से राशि आवंटित की जाएगी।

दरअसल, 3.65 लाख करोड़ रुपए के बजट में लेखानुदान की 1.45 लाख करोड़ की राशि भी शामिल है। सरकार ने मार्च में विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें चार महीने (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस तरह 3.65 लाख करोड की बजट राशि में से 1.45 करोड़ रुपए लेप्स हो जाएंगे। बची हुई 2.20 लाख करोड़ रुपए विभागों को 8 महीने के लिए आवंटित किए जाएंगे।

बजट मैनेजमेंट पर जोर

राज्य का बजट पिछले बार की तुलना में भले ही 16 फीसदी अधिक है, लेकिन सरकारी महकमों को खर्च के लिए भरपूर रकम नहीं मिलेगी। गैर जरूरी खर्चों में कटौती के साथ सरकारी महकमों को जरूरत के मुताबिक ही रकम मिलेगी! सरकार को भरोसा है कि इस बार कमाई में इजाफा होगा। इसके लिए टैक्स लीकेज सुधारने के साथ सिस्टम को भी दुरुस्त किए जाने पर फोकस किया जा रहा है।

विधानसभा के मानसून सत्र में 3.65 लाख करोड़ का बजट पारित हो चुका है। सरकार का टारगेट है कि पांच वर्ष में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। पूंजी निवेश बढ़ाने, सडक, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं को विस्तार करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं एवं रोजगार पर भी फोकस किया गया है। हालांकि सरकार के खर्चों में इजाफा होना तय है, ऐसे में बजट मैनेजमेंट भी तैयार किया है।

अधिक कमाई की उम्मीद

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार अधिक कमाई की उम्मीद है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई सबसे ज्यादा आय जीएसटी, बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर से होगी। इससे मिलने वाला टैक्स 61026 करोड़ रुपए का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में 51557 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मप्र को जीएसटी से 51,557 करोड़ तो 2024- 25 61,026 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

राज्य उत्पाद शुल्क से 2023-24 में 13,845 करोड़, 2024-25 में 16,000 करोड़ स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क से 2023-24 में 10,400 करोड़, 2024- 25 में 12,500 करोड़, वाहन कर से 2024-25 में 2023-24 में 4,440 करोड़, 2024-25 में 5,500 करोड़, विद्युत कर व शुल्क से 2023-24 में 3,858 करोड़, 2024-25 में 5,000 करोड़, अन्य प्राप्तियां से 2023-24 में 2,400 करोड़ और 2024-25 में 2,071 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

महाकाल नगरी में मूर्त रूप लेंगी नटराज की 108 मुद्राएं

उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में होंगी स्थापित मूर्तियां

भोपाल। उज्जैन, जिसे बाबा महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां अब भगवान शिव के ही एक अन्य रूप नटराज की अलौकिक मूर्तियां भी स्थापित होंगी। नृत्य के देवता नटराज को 108 विविध नृत्यों के आविष्कार के लिए जाना जाता है। नृत्य करने वाले शिव सृजन और विनाश दोनों से जुड़े हुए हैं।

जीवन के द्वंद्वों को मूर्त रूप देने वाले नटराज की ऐसी ही 108 मुद्राओं को पहली बार उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में मूर्तियों का रूप दिया जाने वाला है। संस्कृति विभाग के अनुषांग जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी ने इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया है और विभाग को भेजा है। विभाग भी योजना के क्रियान्वयन में जुट गया है और जल्द ही मूर्तियों को तैयार किया जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय के प्रबंधक गौरव तिवारी ने बताया कि शिव और नटराज से जुड़े विभिन्न शास्त्रों के आधार पर अकादमी द्वारा शोध किया गया है। इसमें नटारज की 108 मुद्राओं में समाहित गुणों को आकार दिया जाएगा। उड़ीसा के मूर्तिकारों को नटराज की प्रतिमाओं पर कार्य करने का अनुभव है, इसीलिए कलाकरा ही इन मूर्तियों को गढ़ेंगे। मूर्तियां लाइफ साइज यानि एक इंसान के आकार की होंगी।

इस तरह यह पहली बार होगा कि देश में नटराज की 108 प्रतिमाओं को इस आकार में तैयार किया जा रहा है। गौरव ने बताया कि ग्रेनाइट के पत्थरों को तारशकर मूर्तिकार उन्हें तैयार करेंगे। शिव के नटराज रूप में अनेक संदेश समाहित हैं। वे ऊपरी दाहिने हाथ में एक डमरू धारण करते हैं, जो सभी प्राणियों को उनकी लयबद्ध गति में खींचता है और उनकी ऊपरी बाईं भुजा में वे अग्नि धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। नटराज के एक पैर के नीचे एक कुचली हुई बौने जैसी आकृति है, जो भ्रम और सांसारिक विकर्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। अलंकरण में शिव के एक कान में पुरुष का कुंडल है जबकि दूसरे कान में स्त्री का कुंडल है। यह पुरुष और महिला के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर कहा जाता है।

प्रकृति के सबसे निकटतम और श्रेष्ठ जीवन पद्धति का परिचायक है जनजातीय समाज : तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार

भोपाल। जनजातीय समाज प्रकृति पूजक समाज है। प्रकृति के सबसे निकटतम और श्रेष्ठ जीवन पद्धति का परिचायक, जनजातीय समाज है। उनकी जीवन पद्धति, दर्शन, सभ्यता और विरासत में प्रकृति का महत्व समाहित है। पर्यावरण की वैश्विक चुनौती का समाधान, जनजातीय समाज की जीवन सभ्यता में पारंपरिक रूप से परिलक्षित है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने रविवार को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के नॉलेज रिसोर्स सेंटर स्थित सभागार में जनजातीय विषय पर शोध एवं पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर कही। श्री परमार ने कहा कि सभी को जनजातीय समाज के दर्शन, इतिहास, विरासत संस्कृति, जीवन पद्धति और सभ्यता को जानने के लिए उनके मध्य जाने की आवश्यकता है। जनजातीय समाज में स्वाभिमान का दर्शन मिलता है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जनजातीय समाज के जीवन पद्धति और दर्शन से प्रभावित हैं। जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए जीवन पद्धति और दर्शन पर अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता है। श्री परमार ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सिकलसेल रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए आयुष विभाग अंतर्गत व्यापक कार्ययोजना के साथ कार्य कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में तीव्र गति से क्रियान्वयन हो रहा है। इस अनुक्रम में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को जनजातीय समाज से जुड़े साहित्य से समृद्ध करने की आवश्यकता है। श्री परमार ने कहा कि पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भी जनजातीय समाज से जुड़े समस्त साहित्य भी उपलब्ध होना चाहिए। श्री परमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सघन विकसित करने के उद्देश्य से ही विद्यावन के रूप में अभिनव पहल की गई है। जनजाति शोध एवं अनुशीलन केंद्र नई दिल्ली, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय कार्यशाला हुई।

आलिया से लेकर कैटरीना कैफ तक, इन एक्ट्रेस ने पर्दे पर निभाया रॉ एजेंट का किरदार

हिंदी फिल्म जगत की फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शक जासूसी पर बनी मूवी को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित तमाम फिल्में बड़े पर्दे पर देखने को मिलती हैं। बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स ने रॉ एजेंट का किरदार निभा लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। इसमें सलमान खान की फिल्म टाइगर, किंग खान की पठान, बिग बी की द ग्रेट गैम्बलर और विजय आनंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम जैसी तमाम कलाकार शामिल हैं। जासूसी पर आधारित फिल्मों में न केवल मेल कलाकारों ने भूमिका निभाई बल्कि अभिनेत्रियों ने भी काम किया है। इस आर्टिकल में आज हम आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने रॉ एजेंट के रोल में सिनेमाघरों में धमाल मचाया।

आलिया भट्ट

बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अदाकाराओं में शामिल आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म आल्फा में रॉ एजेंट के रूप में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। इससे पहले वह साल 2018 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म राजी में जासूस की भूमिका निभाई थी। राजी में विक्की कौशल और जयदीप अहलावत की भूमिका देखने को मिली थी।

शरवरी वाघ

कॉमेडी हॉरर फिल्म मुंज्या में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में छाने वाली एक्ट्रेस ने केवल हीरोइन का किरदार निभाया बल्कि रॉ एजेंट के रूप में भी काम कर चुकी है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म महाराज में नजर आई थी। इसके साथ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं।

कैटरीना कैफ

यशराज के बैनर तले बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म टाइगर में कैटरीना और सलमान खान साथ में नजर आए थे। इस फिल्म के तीन पार्ट आ चुकी हैं। टाइगर में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने रॉ एजेंट का किरदार निभाया था।

तापसी पन्नू

साल 2015 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म बेबी में तापसी पन्नू रॉ एजेंट की भूमिका निभाई थी। एक्ट्रेस के साथ अक्षय कुमार मेन लीड रोल में नजर आए थे।

विद्या बालन

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी में विद्या बालन ने गर्भवती महिला का रोल किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस विद्या बागची का किरदार निभाया था। विद्या बागची अपने खोए हुए पति को ढूंढने के लिए रॉ एजेंट की तरह काम करती है।

अमेज़न मिनीटीवी ने 'तुझपे मैं फिदा' सीजन 2 का रोमांचक ट्रेलर रिलीज

मुंबई। अमेज़न का मुफ्त वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा, अमेज़न मिनीटीवी, दर्शकों को कोल टाउन में वापस ले जाने के लिए तैयार है - एक जादुई यात्रा पर जो प्यार, दिल टूटने और रहस्य से भरी हुई है - क्योंकि इसने आधुनिक समय की परियों की कहानी, 'तुझपे मैं फिदा' के दूसरे सीजन की घोषणा की है। पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद, स्ट्रीमिंग सेवा ने आज आगामी सीजन का मोहक ट्रेलर जारी किया, जिससे काफी उत्सुकता फैल गई है। बीबीसी स्टूडियो प्रोडक्शंस इंडिया द्वारा निर्मित, इस सीजन में प्रिय कलाकारों की वापसी हो रही है, जिसमें रुद्राक्ष जैसवाल और निकीत ढिल्लों क्रमशः मार्कस और आइरा की भूमिकाओं में वापस आ रहे हैं। रोमांचक ट्रेलर हमें दिखाता है कि मार्कस और आइरा के बीच जो एक चिंगारी थी, वह अभी भी जीवित है। 'तुझपे मैं फिदा' सीजन 2, 2 अगस्त से विशेष रूप से अमेज़न मिनीटीवी पर मुफ्त में स्ट्रीम होगा, इसे आप अमेज़न की शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, फायर टीवी, स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, हम देख सकते हैं कि ब्रेकअप के बाद वे अपने दिलों को फिर से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द की परछाइयाँ एक काला रहस्य छिपाए हुए हैं।

शुभ योग में सावन की शुरूआत...

इस बार सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। हिन्दू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का विशेष महत्व है लेकिन सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है सावन के महीने में की जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इतना ही नहीं इस बार सावन में विशेष योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना और इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे।

कब से शुरू हो रहा है सावन?

सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024, सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। इस बार सावन के महीने में पांच सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं।

शुभ योगों का संयोग

22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 05: 37 से रात्रि 10: 21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 09:11पर शुरू होगा और 22 जुलाई को सायं 05:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो सायं 05: 58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 02:36 पर समाप्त होगा।

सावन सोमवार की तिथियां

- 22 जुलाई 2024- पहला सोमवार
- 29 जुलाई 2024-दूसरा सोमवार
- 05 अगस्त 2024- तीसरा सोमवार
- 12 अगस्त 2024- चौथा सोमवार
- 19 अगस्त 2024- पांचवा सोमवार

सावन सोमवार का धार्मिक महत्व

सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है इस दिन जो भी मत पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधू प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और इसके अलावा राहु-केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है।

ऐसे करें शिवलिंग का जलाभिषेक

आचार्य दीप कुमार का कहना है कि, श्रावण मास के हर सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक किसी तीर्थ स्थल या गंगा जल से किया जाए, तो इससे भी भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके अलावा शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है. अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर या बीमार महसूस करता है तो उसे शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है. इसके अलावा शिवलिंग पर दहीं चढ़ाने से भी धन संपत्ति से भक्तों को लाभ मिलता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. भगवान शिव को कुश का जल या फिर सुगंधित इतर चढ़ाने से भी व्यक्ति के रोग दूर होते हैं.

इन चीजों का चढ़ाएं चढ़ावा

आचार्य दीप कुमार का कहना है कि अगर सोमवार के दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए, तो इससे सांसारिक सुख भक्तों को मिलता है. वहीं, शिवलिंग पर दूध चीनी मिश्रित जल चढ़ाने से भी बच्चों का दिमाग तेज होता है और उन्हें परीक्षा में सफलता मिलती है. शिवलिंग पर बिल पत्र के पत्ते चढ़ाने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है. इसके अलावा भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है और वंश में वृद्धि होती है. सोमवार को भगवान भोलेनाथ को जौ चढ़ाने से भी कष्ट दूर होते हैं और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है. शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से भक्त के घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती है.

सावन के नियम

- सावन में दाढ़ी, मूंछ, बाल कटवाना वर्जित है.
- भूलकर भी सावन में मांस, मदिरा का सेवन न करें. ब्रह्मचर्य का पालन करें.
- सावन में बैंगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं.
- ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुस्से पर काबू रखें, बुरे विचार मन में न लाएं.
- सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए.

सावन सोमवार पूजा विधि

- शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी गई है. वैसे तो सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है लेकिन सोमवार खास है. पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर लें. सफेद शिव का प्रिय रंग है.
- घर के मंदिर में सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और एक बेलपत्र अर्पित कर तांबे या चांदी के लौटे से जल चढ़ाएं.
- पंचामृत से अभिषेक करें. अभिषेक के समय निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
- शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा,सफेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी पत्र चढ़ाएं. पार्वती जी की भी पूजा करें.
- खीर, हलवे, बेल के फल का भोग लगाएं. घी का चौमुखी दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शिव जी की आरती करें और अंत में प्रसाद बांट दें.

इंदौर नगर निगम बजट 2024-25

महापौर ने शहर विकास के लिए पेश किया

आठ हजार करोड़ का बजट

इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने शहर के विकास के लिए आठ हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान हंगामा करने वाले नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित भी किया।

इंदौर। इंदौर नगर निगम ने शहर के विकास के लिए आठ हजार करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, इस कारण बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। हंगामे के कारण नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। इससे नाराज कांग्रेस पार्षदों ने बजट का बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। इसके बाद मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने बजट भाषण पढ़ा।

आवासीय स्कीम की घोषणा

नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इंदौर में एक आवासीय स्कीम लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा कुछ एरिया में बहुमंजिला भवन भी बनाए जाएंगे। जलकर के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 50 परसेंट की छूट दी। 29 गांव की नजूल की भूमियों पर भी निगम पीपीपी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट लाएगा।

15 साल बाद टैक्स बढ़ाया

इस बार के बजट में जलकर और संपत्तिकर में इजाफा किया गया। जलकर में 100 रुपये बढ़ाए गए और जबकि संपत्तिकर में आवासीय में अधिकतम तीन और कमर्शियल में सात रुपए अधिकतम प्रतिवर्ग फीट वृद्धि की गई। डोर टू डोर कचरा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई। काम काजी महिला को सिटी बस में 75 और विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत छूट दी गई।

कांग्रेस ने किया टैक्स बढ़ाने का विरोध

कांग्रेस पार्षदों ने 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले का विरोध काले कपड़े पहन कर किया। वे तख्ती लेकर परिषद हॉल में जाने लगे तो बाउंसरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बात को लेकर विवाद भी हुआ। टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठ गए।

बजट में की गई घोषणाएं

- 468 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों का विकास होगा। कुल 23 मार्ग बनेंगे। इसमें मास्टर प्लान की तीन सड़कें भी शामिल हैं।
- बजट में डिजिटलाइजेंन पर फोकस किया गया है। निगम खुद का ई पोर्टल तैयार करेगा।
- वेस्ट टू एनर्जी के लिए 200 करोड़ रुपये का नया प्लांट नगर निगम तैयार करेगा। जिसमें 500 टन कचरे का निपटान होगा और छह मेगावाट बिजली भी बनेगी।
- शहर की 30 बस्तियों को ग्रीन स्लम बनाया जाएगा। डेढ़ सौ नए कचरा वाहन डोर टू डोर व्यवस्था के लिए खरीदे जाएंगे।
- शहर के हर वार्ड की एक कॉलोनी को 100 प्रतिशत सोलर बेस्ड किया जाएगा। पांच उद्यानों में भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे।
- इस साल नर्मदा के चौथे चरण का काम शुरू होगा। 27 नई टंकियां बनाई जाएगीं। इस प्रोजेक्ट पर 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इंदौर के पांच इलाकों में आधुनिक पार्किंग बनाई जाएगी।
- इंदौर में कान्हा नदी के शुद्धिकरण के लिए 500 करोड़ के ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे।

मंत्री एवं महापौर द्वारा हैकथान के प्रतिभागियों को किया सम्मानित

इंदौर। योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी श्री राजेश उदावत ने बताया कि नगर निगम इंदौर डिजिटल बनाने के क्रम में दिनांक 26 से 28 जुलाई तक आयोजित प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता हैकथॉन प्रतियोगिता का नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में श्री आनंद मोहन माथुर सभागृह में समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रभारी श्री राजेश उदावत, महापौर परिषद सदस्य श्री राजेंद्र राठौर, श्री अश्विनी शुक्ल, श्री नंद किशोर पहाड़िया, श्री जीतू यादव, श्री निरंजन सिंह चौहान, सुश्री सौम्या जैन, श्री संदीप जैन आईआईटी, पार्षद श्रीमती पूजा पाटीदार, अपर आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ग्रुप चेअरमेन श्री आशीष सोजतियां, श्री गौरव सोजतियां, श्री अतुल भारत, श्रीमती नम्रता तपस्वी, श्री प्रताप नायर, श्री हिमांशु गोयल सहित विभिन्न शहरो के 79 से अधिक युनिवरसिटी/कॉलेज के 500 से अधिक विद्यार्थी/विशेषज्ञ एवं अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रभारी श्री राजेश उदावत जी ने माना। विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहां की मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा अवसर नहीं देखा जहां पर नौजवान पीढ़ी के लिए आज कुछ अवसर मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भरपूर लाभ उठाइए और देश को ताकतवर बनाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान करिए यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में इन्दौर में एक पेड़ माँ के नाम हुए वृहद् पौधरोपण की प्रशंसा की

प्रत्येक नागरिक से अपनी माँ और धरती माँ के नाम पौधा लगाने का किया आह्वान

इन्दौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत मध्यप्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हुए विशेष कार्य का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्दौर में एक ही समय लाखों पौधों का रोपण किया गया है, जो अपने आपमें अनूठा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। देश के अलग-अलग हिस्सों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अच्छे कार्य हुए हैं। स्वच्छता के लिए अपनी पहचान बनाने वाले इन्दौर शहर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में एक वक्त में लाखों पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि अपनी माँ के नाम पेड़ लगाने के इस अभियान से प्रत्येक नागरिक जुड़ें। साथ ही

पौधा लगाने की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर अभियान से जुड़ें। इस अभियान से जुड़कर नागरिकों को अपनी माँ और धरती माँ दोनों के लिए कुछ विशेष कर पाने का अहसास होगा। प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक और युवा भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं।

अभियान के लिए विशेष प्रयास और प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष प्रयास और प्रोत्साहन से मध्यप्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में निरंतर पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें मंत्रीगण, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि सहित आम नागरिक भी पौध-रोपण कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को भी इस अभियान में व्यापक भागीदारी का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी जिलों में पौध-रोपण जारी है। पौध-रोपण के साथ लोग अनके संरक्षण का संकल्प भी ले रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)